(b) The Central Teams visited the drought affected States and on the basis of their assessment of the requirements of the States ceiling of expenditure of Rs. 640 lakhs during 1979-80 and Rs. 1001 lakhs during 1980-81 have been approved for cattle relief.

(c) In July, 1979, i.e., right at the beginning of the drought period, detailed guidelines were issued to the States. This was followed by a meeting of the State Directors of Animal Husbandry of the drought affected States convened in November, 1979 and detailed action points were drawn up for mitigating the effects of drought on Livestock. The guidelines and action points include *inter alia* setting up of cattle camps, arranging dry fodder, forest grasses, damaged foodgrains and groundnut extraction at reasonable prices, cultivating drought resistant varieties of fodder and grass through various promotional schemes, providing health cover and preparation of contingency plans.

Oilseeds Production

*210. SHRI P. K. KODIYAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the production of edible oilseeds in the country is stagnating for the last few years;

(b) if so, what are the details of the production of oilseeds during the last three years; and

(c) what measures are being taken for raising edible oil seeds production?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): (a) No, Sir. Despite fluctuation in the production of edible oilseeds in recent years, the trend has been slightly upward.

(b) The production of edible oilseeds has been 75.7, 85.9 and 91.7 lakh tonnes during the three years 1976-77, 1977-78 and 1978-79 respectively. For 1979-80, estimates of oilseeds production are not yet available but, on current assessment, there is likely to be a decline over the level of the previous year.

(c) The following steps are being taken to increase the production of oilseeds:—

(i) Under Centrally sponsored scheme for oilseeds, an intensive programme is under implementation in ninety districts. Among other things, the scheme aims at demonstrations on farmers' fields, strengthening of seed production arrangements, expansion of plant protection measures and training for farmers and extension workers;

(ii) In addition, States are undertaking oilseeds development programmes from their own funds;

(iii) Increasing the area under short duration varieties of oilseeds through catch cropping and inter cropping; and

(iv) Intensification of research efforts.

हरियाणा में सूखी तथा मरू भूमि के विकास के लिये योजनायें

*211. **श्री मनोहर लाल सेनी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में सूखी तथा मरू भूमि के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि की सहायता मिली है और चालू वर्ष में कितनी सहायता के लिए प्रावधान किया गया है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार हरियाणाट के शुष्क तथा मरू जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरू-भूमि विकास कार्यक्रम को संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, राज्य में शुष्क क्षेत्र में कृषि की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में शुष्क भूमि कृषि के लिए एक समन्वित अनुसंधान परियोजना भी चल रही है।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरुभमि विकास कार्यक्रम	हरियाणा कृषि विश्व-विद्यालय, हिसार में शुष्क भूमि कृषि के लिये समन्वित अनु-सधान परियोजना
1	2	3	4
1977-78	100.00	140.74	2.15
1978-79	187.58	168.00	1.96
1979 80	83.38	48.75	2.82
1980-81†	97 50	195.00	2.88

†बजट प्रावधान

गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया धान

*212. **श्री निहाल सिंह**:क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि.

(क) गत तीन वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितना धान खरीदा गया और क्या उन वर्षों में खरीदा गया धान सुरक्षित भण्डारों को भेजा गया था अथवा जरूरतमंद राज्यों को;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब में लाखों टन धान खली जमीन पर पड़ा है और इस तरह निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि पहुंचाई जा रही है; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव: (क) से (ग). भारतीय खाद्य निगम, जोकि वसूली एजेंसियों में से